ज्वाइन्ट एक्शन कमेटी आफ एशोसिएशन्स/यूनियन्स
ऑफ
बी एस एन एल एक्जीक्यूटिव्स और नान एक्जीक्यूटिव्स
मध्य प्रदेश परिमंडल, भोपाल

कार्यालयः—1195, लाल कोठी, शाही नाका रोड, गढ़ा, जबलपुर—482003
फोनः—2429789 मोबाइलः— 9425124499

संयोजक
एस.आर.नायक

चेयरमेन
आर.के.तोतरे

दिनांक 07.07.2010

प्रधान मंत्री को 19 जुलाई 2010 तक चिट्ठी भेजें

बी एस एन एल को जिन्दा दफना देने की साजिशों के विरोध में बी एस एन एल की पूरी बिरादरी लगातार संघर्षरत है। याद रखने की बात है कि, सन् 2000 में बी एस एन एल के बनने के बाद से ही केन्द्र सरकार बी एस एन एल को बेच देने या कमजोर करने की नीति पर चलती रही है। सन् 2005 में केन्द्र सरकार ने कहा कि केबिल नेट वर्क की अनबन्डलिंग (बीएसएनएल के केबिल नेट वर्क पर निजी कम्पनियों को कनेक्शन देने की सुविधा) करेंगे। किन्तु बी एस एन एल की बिरादरी ने ऐसा नहीं होने दिया। फिर सन् 2006 में केन्द्र सरकार ने कहा कि एकोमोडेशन शेयर (बी एस एन एल के भवनों से निजी कम्पनियों को काम करने की सुविधा) करेंगे। बी एस एन एल की बिरादरी ने इसे भी रोका। फिर केन्द्र सरकार ने कहा कि बी एस एन एल की **10%** हिस्सेदारी बेचेगें। कर्मचारियों ने इसे भी रोका। फिर सरकार ने पितरोदा पैनल की रिपोर्ट के आधार पर कहा कि वह एक लाख कर्मचारियों और अधिकारियों की छटनी करेगी तथा बी एस एन एल की **30%** हिस्सेदारी बेचेगी। इस पर बी एस एन एल की पूरी बिरादरी ने अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां बन्द करके (20 अप्रेल 2010 की हड़ताल) इसे भी रोका।

किन्तु विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के दबाव में आकर केन्द्र सरकार ने 3जी स्पेक्ट्रम शुल्क तथा वायर लेस ब्रॉडबेंड उपयोग शुल्क के नाम पर बी एस एन एल से 18500 करोड़ रूपये झटक लिये। यह एक प्रकार की डकैती जैसी कार्यवाही है तथा इसका परिणाम बी एस एन एल के लिए आर्थिक नाकेबन्दी है। हम इसे भी रोकेंगे।

इसलिए राष्ट्रीय संयुक्त संघर्ष समिति ने माननीय प्रधान मंत्री भारत सरकार को चिट्ठी लिखने (पोस्ट कार्ड भेजने) की आखरी तारीख 05 जुलाई 2010 से बढ़ाकर 19 जुलाई 2010 कर दी है।

इसलिए परिमंडल संयुक्त संघर्ष समिति सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों से अपील करती है कि पोस्ट कार्ड भेजने की कार्यवाही को कोई छोटी कार्यवाही के रूप में न देखें। ध्यान रखें कि यह चिट्ठी, माननीय प्रधान मंत्री जी को चेतावनी का संदेश लेकर जाने वाली है। पुरानी कहावत है कि एक चिट्ठी में सैकड़ों हाथियों के बराबर ताकत होती है।

अतः सभी यूनियने/एसोसिएशनें कृपया सुनिश्चित करें कि 19.07.2010 तक प्रत्येक कर्मचारी और अधिकारी माननीय प्रधान मंत्री जी को पत्र भेजकर उनसे यह आग्रह करे कि बी एस एन एल के 18500 करोड़ रूपये बी एस एन एल को वापिस किए जावें।